आत्मबोधानंद के लिए यह समय संन्यासी से संग्रामी बनने का है प्राण त्यागने का नहीं

जल क्या गंगा के लिए प्राण भी त्याग दें आत्मबोधानंद तो नहीं सुनेगी मोदी सरकार

हिंदू उन्माद को संरक्षण देती मोदी सरकार को 180 दिनों से गंगा बचाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे युवा संन्यासी की मौत से नहीं पड़ेगा कोई फ़र्क, जानिए नदियों की सफाई के दुनियाभर के अनुभव क्या कहते हैं।

महेंद्र पाण्डेय, वरिष्ठ लेखक

हरिद्वार में युवा संन्यासी आत्मबोधानंद गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर अनशन कर रहे हैं, उनके अनशन को 180 दिन से अधिक हो चुके हैं। मानवता के प्रति उनके संघर्ष और त्याग की अदम्य इच्छाशक्ति को हम सलाम करते हैं। मगर मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों को भी बखूबी वाकिफ हैं। वह संग्रामी संघर्ष से तो झुकेगी, लेकिन किसी संन्यासी के प्राण त्याग देने से नहीं। यह वक्त आत्मबोधानंद के लिए संन्यासी से संग्रामी बनने का है और देश भी यही चाह रहा है। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर गंगा और पर्यावरणीय आंदोलनों का अगुवा बनना चाहिए।

अभी तक न तो उनकी सुध किसी ने ली और न ही किसी सरकारी आश्वासन का कोई पत्र उनके पास आया। गंगा की दुर्गति होते जा रही है, वह पहले से अधिक मैली हो गयी है और अब तो हरिद्वार में भी रेत माफिया सरकारी संरक्षण में सक्रिय हो गए हैं।

सरकारी अकर्मण्यता से दुखी होकर अपने अनशन के 178वें दिन, यानि 19 अप्रैल को स्वामी आत्मबोधानंद प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर 27 अप्रैल से जल त्यागने की घोषणा कर चुके हैं। मगर आत्मप्रशंसा में विभोर इस सरकार में उनके पत्र पर कोई भी ध्यान दिया जाएगा, इसकी उम्मीद तो न ही आत्मबोधानंद को होगी और न ही किसी और को। जिस सरकार में अकेले हिन्दू-

उन्माद में, जिसे पूरी तरह सरकारी संरक्षण प्राप्त है, ही अनेक लोग मार दिए जाते हैं, वह सरकार भला एक संन्यासी की मौत पर क्यों ध्यान देगी?

जिस दिन से सरकारें किसी भी विषय पर प्रायोजित खबरें प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में निकालने लगे, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक किसी विषय पर अपनी ही पीठ थपथपाने लगें और सम्बंधित सरकारी संस्थान मंत्रियों के बयान के अनुसार उल्टे-सीधे आंकड़े प्रस्तुत करने लगें तब समझ जाना चाहिए कि जो भी समस्या है वह कभी दूर नहीं होने वाली है।

गंगा नदी के बारे में ऐसा ही हो रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर गडकरी जी और उमा भारती तक सभी अपने दावों में गंगा को साफ करते जा रहे हैं। इनके भाषणों को सुनिए तो और भी आश्चर्य होता है, क्योंकि इनका काम गंगा की सफाई तक कभी पहुंचता ही नहीं है बल्कि घाट बनाने तक ही सीमित रहता है। घाट बनाने से कोई नदी कैसे साफ़ हो सकती है यह तो यही नेता जानते होंगे। दूसरी तरफ, इन नेताओं के बयान पर केन्द्रीय प्रदूषण जैसे संस्थान या तो चुप रहते हैं या फिर इनके दावों के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहते हैं।

मीडिया तो सरकार को खुश करने के अलावा आजकल कुछ करती ही नहीं है। कुछ महीने पहले हिंदुस्तान टाइम्स के लखनऊ संस्करण में कानपुर में गंगा सफाई के बारे में एक कचरा खबर छपी थी जिसे पीएमओ ने अपने वेबसाइट पर भी साझा किया था। इस खबर को यदि किसी स्कूल के विद्यार्थी को भी पढ़ाया जाता तब वह भी अनेक गलतियां ढूँढ लेता। कुछ सप्ताह पहले इकनोमिक टाइम्स ने इसी तरह की खबर से बनारस की गंगा को साफ कर दिया था।

ऐसा नहीं है कि नदियों को साफ करना असंभव है या फिर दुनिया में कहीं भी प्रदूषित नदियाँ साफ नहीं की गयीं हैं। 1980 के दशक में लन्दन के बीचोंबीच बहने वाली थेम्स नदी प्रदूषण का पर्याय बन गयी थी, पर इसे लगभग पांच वर्षों के भीतर ही साफ कर लिया गया। चीन की नदियों में प्रदूषण के स्तर में दो वर्षों के भीतर ही 40 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गयी है।

जर्मनी की एल्बे नदी का पानी केवल प्रदूषित ही नहीं पर विषैला भी था, इसे तीन वर्षों के भीतर ही प्रदूषणमुक्त कर लिए गया। दरअसल सरकारी इच्छाशक्ति और जन-भागीदारी से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। हमारे देश में किसी भी सामाजिक सरोकार के लिए न तो सरकारी इच्छाशक्ति है और न ही जनता की भागीदारी। गंगा का उदाहरण ही देखिये, सरकार के लिए यह मात्र एक वोटबैंक है और जनता के लिए यह समस्या है ही नहीं। शायद ही विश्व में कहीं भी किसी समस्या को लेकर इतना लंबा अनशन चला हो और एक के बाद एक लोगों की अनशन करते हुए मौत होती हो, पर जनता की भागेदारी फिर भी नहीं है।

कुल मिलाकर गंगा सरकारी तौर पर साफ हो गयी है, पर यदि आपको गंगा मैली दिख रही तो यह आपकी समस्या है। जैसे नोटबंदी से भले ही आजतक जनता परेशान हो, पर सरकार इसे सफलता ही मानती है। समस्या और विकट हो जाती है जब सरकार पानी को अपनी मर्जी से नियंत्रित करने लगती है।

अर्धकुम्भ के समय इलाहाबाद में यही किया गया था, ऊपर के बैराज से पानी को छोड़कर नदी में पानी की उपलब्धता तो बनायी गयी, पर नदी के सामान्य बहाव से खूब छेड़छाड़ की गयी। लोगों को नहाने को पानी तो मिला, पर नदी को कितना नुक्सान पहुंचा इसका जिक्र भी किसी ने नहीं किया।

गंगा का नाम जपते रहने का एक सबसे बढ़ा फायदा है, देश की और दूसरी नदियों की चर्चा नहीं होती। इसीलिए सरकार कभी भी इस नदी को साफ नहीं करना चाहेगी। सरकार की नजर में साफ गंगा का मतलब है, इसमें क्रूज की सवारी का आनंद, भव्य गंगा आरती, मालवाहक पोतों की आवाजाही और नदी किनारे सीढ़ियां।

कश्मीर से बंगाल भेजे गए सैनिकों की हालत देख भर आएंगी आपकी आंखें

जनज्वार को सैनिकों ने भेजी हैं तस्वीरें, आप खुद अपनी आंख खोलकर देख लीजिए कि सेना के नाम पर सांप्रदायिकता का ढोल पीटने वाली सरकार की असलियत क्या है, कैसे जानवरों से भी बुरी हालत में सैनिकों को भेजा गया ट्रेन में ठूंस-ठूंसकर।

जनज्वार। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के दौरान जगह-जगह सैनिकों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सेना के नाम पर खूब सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, मगर उनके साथ भेड़-बकरियों जैसा व्यवहार किया जाता है।

यह रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से पश्चिम बंगाल के दौरान ट्रेन संख्या 00696 में की गई यात्रा की है। यह स्पेशल ट्रेन थी, जिसमें उनको स्लीपर क्लास की भी सीटें उपलब्ध नहीं कराई गईं।

3 दिन में यह स्पेशल ट्रेन पश्चिम बंगाल पहुंची। 3 दिन तक यानी 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक भेड़-बकरियों की तरह जनरल डिब्बे में ठूंसे गए सैनिकों ने यात्रा कैसे की होगी, इसकी हम-आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। सैनिक इस मुद्दे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं, शायद उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपना मुंह मीडिया के सामने खोला तो उनका भी हश्र बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की तरह न कर दिया जाये। गौरतलब है कि तेजबहादुर ने अपने वीडियो के जरिए पूरे देश को ये बताया था कि अर्द्धसैनिक बलों को कितना घटिया खाना दिया जाता है। इसके बाद ही तरह तरह से

यह तस्वीरें ट्रेन की जनरल बोगी की है। आंख खोलकर देख लीजिए कि सेना के नाम पर सांप्रदायिकता का ढोल पीटने वाली सरकार की असलियत क्या है, और किस हाल में है सैनिक!

तेजबहादुर यादव को प्रताड़ित करके उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।

पुलवामा के बाद मोदी जहां—जहां भी गए उन्होंने सैनिकों के नाम पर वोट देने की अपील की, मगर जम्मू कश्मीर से पश्चिम बंगाल इलेक्शन ड्यूटी के लिए इस भयानक गर्मी में सैनिकों को ट्रेन की जनरल बोगी में ऐसे-ऐसे ठूंस-ठूंसकर ट्रेनों में भेजा गया मानो वो इंसान ही न हों। सांप्रदायिकता की हद तक सैनिकों की मौत को भुनाने वाली मोदी सरकार को क्या सैनिकों को यह दुर्दशा नहीं दिखाई दी कि जम्मू कश्मीर से पश्चिम बंगाल की यात्रा सैनिक इन हालातों में कैसे करेंगे।

मोदी जी के भाषण सुनकर सैनिकों के नाम पर वोट देने से पहले जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए।

ये तस्वीरें तो सिर्फ एक डेमो हैं, हर जगह सैनिकों की यही हालत है। पुलवामा में ही अगर सैनिकों को हवाई जहाज से भेज दिया जाता तो शायद हमारे 46 जवान आतंकी हमले की भेंट न चढ़े होते। मगर मोदी सरकार अपनी इन नाकामियों को स्वीकारने और सैनिकों को सुविधायें मुहैया कराने के बजाय सिर्फ उनके नाम पर राजनीति करना जानती है।

हमारे प्रधानमंत्री मोदी जहां खुद अपनी हवाई और विदेश यात्राओं के लिए अच्छा खासा बजट खर्च करते हैं, वहीं सवाल है कि जिनके नाम पर वह वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कम से कम उन्हें न्यूनतम सुविधाएं तो उपलब्ध करवाते। वोट पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ रहे सैनिक इस हाल में जनरल बोगी में यात्रा करने को हैं मजबूर।

ईएसआई मेडिकल कॉलेज ने फ़िर बाज़ी मारी, क्विज में 40 टीमों को पछाड़ा

फ़रीदाबाद (म.मो.) सालाना परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद, इस कॉलेज की तीन सदस्यीय टीम ने 25 अप्रैल को हुए गायनी यानी स्त्री रोग से सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के एक क्विज में देश भर से चुन कर आई 42 टीमों में से 40 को पछाड़ कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहला स्थान प्राप्त करने वाली एआईएमएस (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) दिल्ली की टीम को भी यह स्थान आसानी से प्राप्त नहीं करने दिया। इसके लिये एआईएमएस की टीम के पसीने छुड़ा दिये थे। पहले स्थान के लिये लम्बी टसल चलने के बाद टाइ ब्रेकर की नौबत आ गयी। इस स्थिति में पहुंच कर बड़ी मुश्किल से एआईएमएस जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की टीम प्रथम स्थान प्राप्त कर पाई।

मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थियों में उनकी शैक्षनिक योग्यता एवं रुचि बढाने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थान इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। यह आयोजन दिल्ली स्थित जामिया हमदर्द ने आयोजित किया था, जिनका अपना मेडिकल कॉलेज इस प्रतियोगिता में कोई स्थान नहीं पा सका।

देश भर से आई 42 टीमों में से अधिकांश तो प्रारम्भिक राऊंडों में ही छट कर बाहर हो गयी थीं। बची हुई 11 टीमों में दिल्ली के तमाम प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों की टीमें शामिल थीं। इनमें हरियाणा राज्य से एकमात्र ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की टीम थी। एआईएमएस जैसे देश के अति प्रतिष्ठित संस्थान को इतनी कड़ी टक्कर देने के लिये यह टीम वाकइ बधाइ की पात्र है।

श्रीलंका में इस्लामी आतंकवाद

जो भयानक रूप सामने आया है उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है । भयानक आतंकी काम करने वाले अपने आप को इस्लाम से जुड़ा हुआ कहते हैं यह और अधिक चिंता की बात है। गहरी चिंता की बात उनके लिए और अधिक है तथा उनकी जवाबदेही बनती है जो अपने आपको इस्लाम धर्म का व्याख्याकर कहते हैं और जो इस्लाम धर्म के धार्मिक गुरु कहे जाते हैं। जो यह दावा करते हैं कि इस्लाम सुलह,शांति और मानवता का धर्म है। जो यह मानते हैं कि इस्लाम सभी धर्मों का सम्मान करता है।

पूरा संसार यह जानना चाहता है कि ये आतंकी कैसे मुसलमान है? किस इस्लाम को मानते हैं ? उनकी ट्रेनिंग कहां होती है? इनको इस्लाम का आतंकी पाठ कौन पढ़ाता है ? इनको इतना पागल कैसे बना दिया जाता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवक भयानक निर्दयी इस्लामी आतंकी बन कर आत्मघाती हमलों में सौकड़ों मासूम लोगों को मार डालता है? इस्लाम एक अंतरराष्ट्रीय धर्म है और धर्म गुरुओं की कमी नहीं है। ऐसे देशों की भी कमी नहीं है जो अपने आप को इस्लामी देश कहते हैं। क्या यह उन सब का फर्ज नहीं बनता कि इस्लाम के नाम पर संसार में जो आतंक फैलाया जा रहा है उसकी न सिर्फ भर्त्सना और निंदा करें बल्कि कोई ऐसा कारगर उपाय करें कि इस्लाम के नाम पर आतंकवाद की ट्रेनिंग पर लगाम लग सके। ऐसी मस्जिदों, मदरसों और आतंकी धर्म गुरुओं की पहचान की जाए। उनके आतंकी इस्लाम प्रचार को चुनौती दी जाए । क्या यह इस्लामी धर्म गुरुओं का काम नहीं है? यदि वे यह काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और यदि वे यह काम नहीं करेंगे तो उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा?

वैचारिक और सैद्धान्तिक आधार पर इन आतंकी गुटों से संघर्ष करने के अलावा उन देशों की आर्थिक नाकेबंदी आदि करने और उन्हें मजबूर करने की आवश्यकता है कि वे आतंकवाद को बढ़ावा न दें । जो देश इन आतंकी गुटों को पैसा आदि देते हैं उनका पूरी दुनिया बहिष्कार करे।

संसार तेल के बिना रह सकता है पर आतंकवाद के साथ नहीं रह सकता।

– असग़र वजाहत